किया जा रहा है इसके परिणामस्वरूप 7वी योजना के दौरान चने को 17, अरहर को 7, मूग को 8, मटर की 5, मसूर की 4 किस्में और उडद, मोठ और लोबिया प्रत्येक की दो-दो किस्मे विकसित की गई हैं । इन किस्मों के प्रजनक आधारों और प्रमाणीकृत बीजों का उत्पादन और वितरण प्रारंभ किया गया है ।

उत्तर प्रदेश, बिहार, उडीसा, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि राज्यों मे अरहर, मूग, उडद और लोबिया की अल्पावधि किस्मो को आरंभ करके बहुसस्य पद्धति के संवर्धन मे ये किस्मे सहायक सिद्ध हुई है।

खाद्य तेलों की कमी

1135. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 अक्तूबर, 1990 के "फाइनैन्सियल एक्सप्रेस मे "एडीबुल आयल शार्टेज टू टच 13 एल टी. इन 1990-91" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष देश मे खाद्य तेलों के उत्पादन के बारे मे सरकार के क्या अनुमान हैं ,

(ग) क्या सरकार ने इस वर्ष देश में खाद्य तेल की खपत के बारे मे कोई मूल्यांकन किये हैं ; और

(घ) सरकार दालों की मांग और पूर्ति के बीच के अंतर को कम करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार रखती है ;

कृषि मंत्रालय में और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्ती लाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) खरीफ तिलहनों का उत्पादन अनुमानत 87 लाख मीटरी टन है । रबी मे उत्पादन की आशा अनुकूल है परन्तु वर्तमान चरण पर पक्के अनुमान देना संभव नही है । इसलिये इस समय यह कहना संभव नही है कि इस वर्ष देश मे खाद्य तेलों का उत्पादन कितना होगा ।

(ग) तेल वर्ष 1990-91 मे देश मे खाद्य तेल की माग करीब 60 लाख मीटरी टन होने की आशा है ।

(घ) सरकार, तिलहनो के उत्पादन और खाद्य तेल की उपलब्धता बढ़ाने के लिये तिलहन उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है । तिलहन परिसंस्करण और निष्कर्षण की क्षमता बढ़ाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं । इस अतर को कम करने के लिये खाद्य तेल के आयात पर भी विचार किया गया है ।

दिल्ली मे वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि

1136. **श्री बलराम सिंह यादव :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 अक्तूबर, 1990 के हिन्दुस्तान टाइम्स मे "शार्प इनक्रीज इन वनस्पति प्राइसेस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, और यदि हा, तो दिल्ली मे जुलाई, 1990 से अक्तूबर, 1990 के बीच वनस्पति के मूल्यों मे कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1990 में त्यौहारों के मौसम के दौरान वनस्पति के दामों में अत्यधिक वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली मे अक्तूबर, 1990 मे वनस्पति के मूल्य क्या थे ; और

(घ) मूल्यों में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या हाल में प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरवर हुसैन) : (क) जी हां, जुलाई, 1990 से अक्तूबर, 1990 तक दिल्ली में लोकप्रिय ब्राडो के वनस्पति के मूल्यो में लगभग 17 प्रतिशत वृद्धि हुई थी ।

(ख) जी हा ।

(ग) दिल्ली मे रथ और डालडा वनस्पति की 1 कि. ग्रा. की थैली के मूल्य दिनाक 31 अक्तूबर, 1990 को क्रमश. 38.65 रुपये और 39.30 रुपये थे ।

(घ) सरकार द्वारा कीमतो को कम करने के लिए उठाए गए कुछ प्रशासनिक कदम इस प्रकार हैं :—

1. वनस्पति के विनिर्माण मे लघु/गैर-परम्परागत तेलो के प्रयोग पर उत्पाद शुल्क मे छूट दी गई है ;

2 थोक और खुदरा विक्रेताओ के पास हाइड्रोजनित वनस्पति तेलो की स्टाक सीमा घटाई गई है ;

3. उत्पादको के पास खाद्य तेलो और वनस्पति की स्टाक सीमाए घटा दी गई है ,

4. कम की गई स्टाक सीमाओ को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे नियमित आधार पर जमाखोरी विरोधी अभियान चलाएं ।

दिल्ली हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी समिति द्वारा सहकारी आवास समितियों को ऋण

1137. **श्री बलराम सिंह यादव :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनाक 13 दिसम्बर, 1990 को जनसत्ता में "जब कर्ज ही नहीं मिलेगा तो मकान कहा से बनेंगे" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल मे दिल्ली की लगभग 400 सहकारी आवास समितियों को भूमि के आबंटन के बारे मे अपनी योजना को कार्यान्वित किया है जब कि दिल्ली हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी ने आवास निर्माण के लिये केवल 250 करोड रुपये की ऋण राशि ही निर्धारित की है ,

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ऋण की राशि बढ़ाने का विचार रखती है ,

(घ) यदि नही, तो उसके क्या कारण है और प्रत्येक समिति को हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी द्वारा ऋण की कितनी-कितनी राशि दिए जाने की सभावना है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) जी, हा ।

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में 423 सहकारिता सामूहिक आवास समितियों को पप्पनकलां/नरेला में भूमि आवंटन के लिए प्रस्ताव-पत्र भेजे है ।

दिल्ली सहकारी आवास वित्त समिति लिमिटेड ने, जो कि सहकारी सामूहिक आवास समितियो की ऋण आवश्यकताए पूरी करता हैं, आठवी पचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं से निधि की पूर्वानुमानित उपलब्धता के आधार पर 250 करोड रुपये की राशि उद्दिष्ट की है । सहकारी सामूहिक आवास समितियो की ऋण आवश्यकता पूरी करने वाली यह अकेली संस्था नहीं है । जीवन बीमानिगम, आवास वित्त निगम, हुडको, एच. डी. एफ. सी., कैन फाइनेन्स होम बैंक इत्यादि जैसी अन्य संस्थाए भी हैं जो सहकारी सामूहिक आवास समितियों की ऋण आवश्यकताओं को पूरी करती हैं । सरकार ने भी देश मे आवास वित्त संस्थाओं के कार्यकलापो मे